भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2819
17.12.2025 को उत्तर देने के लिए

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2025

2819. श्री रमेश अवस्थीः
श्री हरीभाई पटेलः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवंबर 2025 में किए गए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त प्रमुख श्रम बाजार संकेतक क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2025 में किए गए पद्धतिगत संशोधनों के बाद पीएलएफएस डेटा की आवृत्ति, कवरेज और सामयिक प्रसार में सुधार करने के लिए कदम उठाए है

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) भावी सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के लिए अद्यतन राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी)-2025 का क्या महत्व हैं;और

(ङ) एनआईसी- 2025 के उपयोग से श्रम बाजार और आर्थिक आंकड़ों की सटीकता, तुलनीयता और नीतिगत उपयोगिता में किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): अक्तूबर 2025 के नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मासिक बुलेटिन से, अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष, महिला और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण+शहरी संयुक्त में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

अक्तूबर 2025 के लिए पुरुष, महिला और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर प्रतिशत में

क्षेत्र	सीडब्ल्यूएस में एलएफपीआर			सीडब्ल्यूएस में डब्ल्यूपीआर			सीडब्ल्यूएस में यूआर		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ग्रामीण	78.4	38.4	57.8	74.8	36.9	55.2	4.6	4.0	4.4
शहरी	75.3	25.4	50.5	70.8	22.9	47.0	6.1	9.7	7.0
ग्रामीण+शहरी	77.4	34.2	55.4	73.4	32.4	52.5	5.1	5.4	5.2
स्रोत: मासिक बुलेटिन , पीएलएफएस, अक्टूबर, 2025									

(ख) और (ग): पीएलएफएस के प्रतिदर्श डिज़ाइन को जनवरी 2025 से इसकी वर्धित कवरेज के साथ उच्च आवृत्ति श्रम बाजार संकेतकों की अपेक्षाओं को संबोधित करने के लिए संशोधित किया गया है। पीएलएफएस की प्रतिदर्श पद्धति में परिवर्तन के मुख्य पहलू नीचे दिए गए हैं:

आवृत्ति: संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिज़ाइन से अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) दृष्टिकोण का पालन करते हुए मुख्य श्रम बाजार संकेतकों यथा एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर के मासिक अनुमान तैयार किए गए है। अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक के मासिक बुलेटिन जारी कर दिए गए हैं। दिसंबर 2024 तक, पीएलएफएस ने केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही श्रम बाजार संकेतक उपलब्ध कराए हैं। संशोधित पीएलएफएस में, रोजगार-बेरोजगार संकेतकों का तिमाही अनुमान पूरे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है । अप्रैल-जून 2025 और जुलाई-सितंबर 2025 के तिमाही बुलेटिन जारी कर दिए गए हैं।

कवरेज: पीएलएफएस देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करता है। संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिज़ाइन में, जिले को प्राथमिक भौगोलिक इकाई बनाया गया है, जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मूल स्तरीय इकाई कहा जाता है, ताकि ज्यादातर भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए एफएसयू का चयन किया जा सके। शेष क्षेत्र में, एनएसएस क्षेत्र को मूल स्तरीय क्षेत्र बनाया गया हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि पीएलएफएस प्रतिदर्श में अधिकांश जिलों से प्रतिदर्श अवलोकन मौजूद हों, जिससे तैयार किए गए अनुमानों की प्रतिनिधित्व क्षमता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिदर्श का आकार दिसम्बर, 2024 तक सर्वेक्षण किए गए 12,800 एफएसयू (एफएसयू– प्रतिदर्श गाँव/शहरी ब्लॉक/उप-इकाइयाँ) से 22,692 प्रथम चरण इकाइयों तक बढ़ा दिया गया है और प्रतिदर्श परिवारों की संख्या भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। बढ़ाए गए प्रतिदर्श आकार से श्रम बाजार के संकेतकों के विश्वसनीय अनुमान अधिक सटीकता के साथ प्राप्त होने की आशा है।

समय पर प्रसार: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अग्रिम जारी किए गए कैलेंडर (एआरसी) में निर्धारित समयसीमा के अनुसार पीएलएफएस के परिणाम समय पर जारी किए जा रहे हैं।

(घ) और (ड.): चालू पीएलएफएस एनआईसी 2008 के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में नवंबर 2025 में एनआईसी 2025 जारी किया है। एनआईसी 2025 में एनआईसी 2008 की 5-अंक-स्तरीय संरचना के स्थान एक नई 6-अंक-स्तरीय कोडिंग अवसंरचना प्रस्तुत की गयी है और यह भारत में आर्थिक कार्यकलापों को वर्गीकृत करने के लिए नवीनतम अद्यतन राष्ट्रीय मानक का पालन करता है, जो सभी आर्थिक कार्यकलापों के लिए एक व्यापक और आधुनिक अवसंरचना प्रदान करता है, जो तकनीकी प्रगति, नवाचार और नए उभरतें क्षेत्रों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से होने वाले परिवर्तन को कैप्चर करता है। यह उभरते कार्यकलापों के बेहतर प्रतिनिधित्व और श्रम बाजार और आर्थिक सांख्यिकी की सटीकता, तुलनीयता और नीति उपयोगिता में सुधार करता है।

*****